pay any tax or pay marginal tax, several thousand assessment records are required to be individually scrutinised. The time, efforts and expenditure to collect the information will not be commensurate with the results sought to be achieved.

(b) and (c) In view of the Budget secrecy; it would not be proper at this stage, to furnish information in respect of Budget proposals.

(d) No separate statistics regarding tax received from Public Sector companies are maintained. However, figures of Corporate Tax received during the last three years are as under:—

	(Rs. in crores)
1992-93	8889.24
1993-94	10060.06
1994-95	13821.00

Closure of Textile Mills in Ahmedabad

*331. SHRI AHMED PATEL:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether as a result of closure of textile mills in Ahmedabad some 40,000 workers have been rendered jobless;

(b) if so, what steps have since been taken for payment of statutory dues to them; and

(c) whether Gujarat Government had proposed that Union Government may take over the assets of these sick textile mills and revive them by pooling their resources and granting loans for payment of statutory dues to the workers; if so, Government's decision thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI KAMAL NATH): (a) to (c) According to the Minister of Industry the Government of Gujarat has submitted a proposal to the Ministry of Industry for grant of assistance from the National Renewal Fnnd for Area Regeneration Scheme for 19 closed textile mills under liquidation. The proposal envisages (inter-alia) take-over of the assets of these mills by the State Government, payment of legal dues to the 30,150 employees of the mills, retraining of jobless employees, incentive for area regeneration and utilisation of assets of closed mills, etc. The matter of payment of statutory dues or taking over of assets by the state Government, comes under the jurisdication of the state Government.

विभिन्न विमानपत्तनों से जब्त की गयी वस्तुएं

332. **श्री नागमणि:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न विमानपत्तनों से 1 जनवरी से 30 नवम्बर, 1995 के बीच जब्त की गयी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन वस्तुओं को बेच दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जब्त की गयी वस्तुओं के निपटान हेतु सामान्यतः अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ख) पहली जनवरी से 30 नवम्बर, 1995 तक की अवधि के दौरान देश में अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर 92.83 करोड़ रुपये मूल्य का सोना चांदी, विदेशी मुद्रा, कैमरे, वी०सी०आर०, सर्प चर्म, स्वापक औषध द्रव्य, बहुमूल्य रत्न, घड़ियां और घड़ियों के पुर्जे, कम्प्यूटर के पुर्जे, सेलुलर फोन आदि पकड़े गये थे। इसी अवधि के दौरान विमानपत्तनों पर पकड़े गये और/या जब्त किये गये 101.08 करोड़ रुपये के माल को बेचा गया।

पकड़े गये माल को सामान्यतः जब्ती संबंधी कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर बेच दिया जाता है। किन्तु शीघ्र खराब होने वाले तथा ज्यादा देर तक न रखे जा सकने वाले माल का अभिग्रहण करने के बाद शीघ्र ही निपटान कर दिया जाता है।

जब्तशुदा उपभोक्ता माल को, जो निपटान के लिए तैयार पड़ा होता है, सीमाशुल्क के काउंटरों पर अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और उपभोक्ता सहकारी